



कौन कहता है कि गोवर्धन सिंह अकेला है राजस्थान ही नहीं पूरे देश से माननीय राज्यपाल के नाम असंख्य ज्ञापन व विरोध पत्र लगातार जारी हो रहे हैं एडवोकेट गोवर्धन सिंह की कमाई 23 करोड़ हो ना हो लेकिन भारत के करोड़ों लोगों की दुआएँ उनके खाते में दर्ज हैं जिसका सशक्त प्रमाण कुछ चुनिंदा ज्ञापन व तस्वीरें यहाँ शेयर की जा रही हैं। होने को असंख्य ज्ञापन व विरोध पत्र हैं, सभी को छापना सम्भव नहीं लेकिन यह अभियान एक आन्दोलन बन कर पूरे देश में उभरने लगा है। लगातार झूठी एफआईआर और सोये पड़े हुए मुद्दे सर उठाने लगे हैं लेकिन क्या सत्यता का प्रकाश झूठ के अंधकार को मिटा नहीं देगा। महाराष्ट्र से लेकर मध्यप्रदेश तक और दिल्ली से लेकर राजस्थान के एक छोटे गाँव तक इस आन्दोलन की चिंगारी पहुँच चुकी है जिसे बुझा पाना सियासी ताकतों के वश में नहीं।



नवी मुंबई से व्यापारियों द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम अधिवक्ता गोवर्धन सिंह के समर्थन में ज्ञापन तैयार कर स्पीड पोस्ट से भिजवाया गया। (हिलव्यू समाचार)



सुनवाई के दौरान जयपुर कोर्ट के बाहर गोवर्धन समर्थक अधिवक्ताओं की अच्छी खासी भीड़ जमा होती है और परिसर में इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूँजन लगते हैं। क्या अब भी राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सकरात्मक सहयोग की आवश्यकता है? (हिलव्यू समाचार)



जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर की द बार एसोसिएशन ने एडवोकेट गोवर्धन सिंह व सहयोगी वकील साथियों को पुलिस व सरकार द्वारा झूठे मामलों में प्रताड़ित करने के विरुद्ध ज्ञापन दिया व अधिवक्ता साथियों ने बैठक कर इस तानाशाही के खिलाफ मिल कर आवाज उठाने का निर्णय किया। (हिलव्यू समाचार)



समर गौड़ RTI ने राजस्थान पुलिस, प्रशासन एवं सरकार द्वारा गोवर्धन सिंह के साथ की जा रही प्रताड़नाओं, अन्याय व अत्याचार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दिल्ली के समक्ष विस्तार से रखा। माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव राजस्थान से इस पर दिनांक 17.05.2022 तक रिपोर्ट तलब की है। (हिलव्यू समाचार)

**पंकज जोया**  
पूर्व सदस्य  
संस्थापक सदस्य

**केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड**  
युवा एवं प्रसारण मंत्रालय  
नई दिल्ली, भारत सरकार

क्रमांक :- 13/2022  
महामहिम राज्यपाल महोदय  
जयपुर - राजस्थान

दिनांक :- 04.05.2022

विषय :- आरटीआई एक्टिविस्ट अधिवक्ता श्री गोवर्धन सिंह के विरुद्ध राजकीय हेतु से प्रेरित होकर दर्ज करार एवं सभी मुकदमों में निष्पक्ष अनुसंधान करवाने उनके परिवार के सदस्यों व साथियों को बेवजह से गिरफ्तार करवाये जाने के संबंध में।

महोदय,  
उपरोक्त विषय अंतर्गत जोय है कि आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट श्री गोवर्धन सिंह राजस्थान सरकार व पुलिस के विरुद्ध प्रकरणों में पुरस्कार से वंचित करके हैं तथा प्रशासन से भीड़ जमा करके की जामानत बकाया का पीछा अत्याचार को जबरन दबाने का काम करते रहे हैं जो अत्यंत गंभीर व गंभीर है। जोय है कि गोवर्धन सिंह के अतिरिक्त के प्रति अत्याचार करने का कार्य करी ही कुशलतापूर्वक करके है जिसके कारण इसके पीछे चले की संख्या अज्ञात में है इसी कारण राज्य सरकार व पुलिस विभाग को उनके अधिकारों को सिद्ध को झूठे मुकदमों में गिरफ्तार करवाये जाने को उनके अधिकारों के मुद्दों को जमानतों से वंचित करवा चकरी है।

अतः श्रीमान को निवेदन है कि अधिवक्ता श्री गोवर्धन सिंह के विरुद्ध राजकीय हेतु से प्रेरित होकर दर्ज करार एवं सभी मुकदमों में निष्पक्ष अनुसंधान करवाने तथा उनके परिवार के सदस्यों व साथियों को बेवजह से गिरफ्तार व प्रताड़ित करने के संबंध में अधिकारों को सिद्ध किया जाये।

धन्यवाद

प्रतिनिधि आवेदक कार्यवाही एवं मुकदमों :-  
:- श्रीमान पुलिस महादेशिक महोदय, जयपुर पुलिस ( जयपुर इलेन )

Scanned by TapScanner

**गोवर्धन सिंह के लिए एक माँ की दुआ**

4 मई को अधिवक्ता गोवर्धन सिंह को पुलिस ने माननीय न्यायालय में पेश किया उस समय न्यायालय परिसर में शाहीन आँखों में आंसू लिए बैठी थी। किसी वकील साथी ने उस बूढ़ी माँ से रोने और कोर्ट परिसर में आने का कारण पूछ तो अपने 2 बेटों के साथ आयी उस माँ ने बताया कि साहब मेरे दोनों बेटे जेल में थे और हम बहुत गरीब होने के कारण अपने बेटों की जमानत नहीं करवा पा रहे थे फिर हमें हमारे किसी जानकार ने वकील साहब गोवर्धन जी के पास भेजा वकील साहब ने हमारे हालात को देखते हुए 1 रुपया भी फीस नहीं ली और मेरे दोनों बेटों की जमानत हाईकोर्ट से करवा दी। कोर्ट परिसर में जब उस बूढ़ी माँ को अधिवक्ता गोवर्धन सिंह से मिलवाया गया तो वो फूट-फूट कर रोने लगी और उनके लिए दुआ करने लगी। (हिलव्यू समाचार)

वीकानेर विधि छात्र हेमन्त कातेला व उसके साथी समूह ने राज्यपाल को गोवर्धन सिंह गिरफ्तारी के विरोध में ज्ञापन दिया एवं अधिवक्ताओं के प्रति इस प्रकार होने वाले कुच्यवहार एवं राजनैतिक द्वेषपूर्णता की घोर निंदा की। (हिलव्यू समाचार)

**वीरेंद्र राजपुरोहित, पाली**

मैं एक पत्रकार हूँ। एक मामले में मैंने एक श्रमिक नेता रामनाथ सिंह की संदिग्ध मौत पर सच्चाई लिखकर खबर चलाई जिसमें श्रमिक नेता के पुत्र ब्रजमोहन सिंह ने पाली पुलिस के कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि मेरे निदोष पिता को पुलिस ने कस्टडी के दौरान भयंकर मारपीट की जिस वजह से मेरे पिताजी की मौत हुई है यह खबर लगाते ही तत्कालीन पाली SP राहुल कोटोकि IPS व थानाधिकारी गौतम जैन ने एक षडयंत्र के तहत मेरे ऊपर भी एक फर्जी केस कर दिया और मेरी भी हत्या की साजिश रच डाली लेकिन मैं पाली से निकल गया। इस मामले में मेरी एडवोकेट गोवर्धन सिंह व एडवोकेट रज्जक हैदर ने बहुत मदद की। इन्होंने हाइकोर्ट जोधपुर में मेरी निःशुल्क पैरवी कर मुझे राहत दिलवाई मुझसे आज दिन तक गोवर्धन सिंह जी ने एक रुपया नहीं लिया वकील साहब अच्छे, सच्चे, नेकदिल आदमी है हमेशा गरीबों की मदद करते हैं भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ बुलंदी से आवाज उठाते हैं। (हिलव्यू समाचार)

पंकज जोया, पूर्व सदस्य केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड नई दिल्ली एवं प्रदेश उपाध्यक्ष राज्य भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानव अधिकार संगठन ने अधिवक्ता गोवर्धन सिंह की अवैध गिरफ्तारी व स्वच्छ अनुसंधान के सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल व पुलिस महानिदेशक व IG सिविल रॉट्स को पत्र लिखा है। (हिलव्यू समाचार)



बोदासर तहसील से युवा वर्ग और परमेश्वर पिलानियां टीम ने माननीय राज्यपाल हेतु एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। (हिलव्यू समाचार)



विकलांग हो या विधवा महिला, जरूरतमंद हो या गरीब किसान गोवर्धन सिंह ने सभी को उसी तरह ट्रीट किया जैसे अपने सक्षम क्लाइंट्स को करते हैं। विकलांग व्यक्ति की प्रासिडिंग के लिए ऑफिस के बाहर सीढ़ी पर बैठ कर भी काम को अंजाम देते रहे हैं गोवर्धन सिंह। (हिलव्यू समाचार)



बगरू (जयपुर) में एडवोकेट महेंद्र कुमार शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमार, बालकिसराम, विजय साहू, गोपाल सोनी, कैलाश सिंह, शिवराम कुमावत आदि व्यापारियों ने मिलकर महामहिम राज्यपाल महोदय, जयपुर को जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट गोवर्धन सिंह के खिलाफ विधि विरुद्ध तरीके से की जा रही कार्यवाही को रोकने की मांग की। (हिलव्यू समाचार)



अधिवक्ता गोवर्धन सिंह के ऊपर सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय के विरोध में लूणकरणसर के जागरूक अधिवक्ता एवम साथीगण द्वारा माननीय राज्यपाल के नाम से उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दे कर निष्पक्ष अनुसंधान करने एवम पुलिस द्वारा अधिवक्ता साथियों एवम उनके पारिवारिक सदस्यों को किए जा रहे बेवजह परेशान करने को रोकने का निवेदन किया तथा साथ में ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया कि यदि पुलिस द्वारा ऐसे झूठी एफआईआर की जाती रही तो लूणकरणसर में सरकार के विरोध में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। (हिलव्यू समाचार)



**सलमा, पाली**

सलमा का कहना है कि वह पाली में 2017 से लगातार जुआ सट्टे के खिलाफ आवाज उठा रही है जिस कारण उस पर अब तक तीन बार प्राणघातक हमले हो चुके हैं। 3 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यालय व निवास पर जाकर परिवार दे चुकी है, लेकिन उसकी एक बार भी सुनवाई नहीं हुई, न न्याय मिला। उसके बाद एडवोकेट गोवर्धन सिंह ने पूरी मदद की एक रुपया नहीं लिया और सलमा का पाली में केस भी निःशुल्क लड़ रहे हैं। मैं उनके लिए न्याय की दुआ करती हूँ। (हिलव्यू समाचार)



ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बहादुरवास, पंचायत समिति मण्डवा, जिला झुन्डू को बहादुरवास पंचायत के सरपंच श्री ब्रजेश सेवदा व अन्य कार्यकर्ता ने एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में निष्पक्ष जांच के लिए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। (हिलव्यू समाचार)



**चूरू अधिवक्ता संगठन**

अधिवक्ता गोवर्धन सिंह के मामले में चूरू जिला कलेक्टर को वहाँ के अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर सरकार द्वारा दुर्भावना व उनके विरुद्ध की जा रही कार्यवाही को रोकने की मांग की है। (हिलव्यू समाचार)



जैसलमेर बीजेपी नेता पूर्व विधायक छोटू सिंह भाटी ने गोवर्धन सिंह की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया है और जनता के साथ सड़क पर उतर आए हैं और कहा है कि सरकार ने अपनी नाकामी के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक ईमानदार और क्रांतिकारी गोवर्धन सिंह को गिरफ्तार कर अपनी तानाशाही का परिचय दिया है। (हिलव्यू समाचार)



फुतेहपुर (सीकर) के राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मानवाधिकार संगठन ने माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर सरकार को चेताया है। (हिलव्यू समाचार)



अधिवक्ता गोवर्धन सिंह के मामले में युवा अधिवक्ताओं सहित आमजन ने दिया ज्ञापन: श्री कोलायत जी के युवा अधिवक्ता दिलीप सिंह राजपुरोहित एवं साथी अधिवक्ताओं, आमजन ने उपखंड अधिकारी कोलायत को ज्ञापन देकर अधिवक्ता गोवर्धन सिंह की गिरफ्तारी के मामले में विरोध प्रदर्शन किया और एडवोकेट गोवर्धन सिंह को न्याय दिलाने की मांग की। (हिलव्यू समाचार)



महाजन (बीकानेर) में सामाजिक कार्यकर्ता विक्रमसिंह राठौड़, हनुमान जससु, रामकुमार जी लाटा, विनोद सारस्वत, शिवलाल ओझा, रणजीत सिंह रामबाग, मदन मोट, सावन पुरोहित, कैलाश रंगा, कैलाश पुरोहित, पवन सारद, हरिराम देहर, बलराम जससु, रघुनाथ शर्मा, राजेश गोस्वामी, रामकुमार भारती, शिव ठाकरानी, संजय राठी, व आस पास के क्षेत्र के युवाओं व मातृशक्ति ने मिलकर महाजन, नाथन तहसीलदार को महामहिम राज्यपाल महोदय, जयपुर के नाम ज्ञापन दिया। (हिलव्यू समाचार)

पूरे देश से 1000 आरटीआई कार्यकर्ताओं ने गय हस्ताक्षर विरोध दर्ज किया है। 1000 कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर को छापना संभव नहीं किंतु अपने ज्ञापन में उन्होंने सूचना के अधिकार पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर प्रश्न उठाया है और गोवर्धन सिंह के समर्थन में माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेजा है।

**सपना, श्रीगंगानगर**

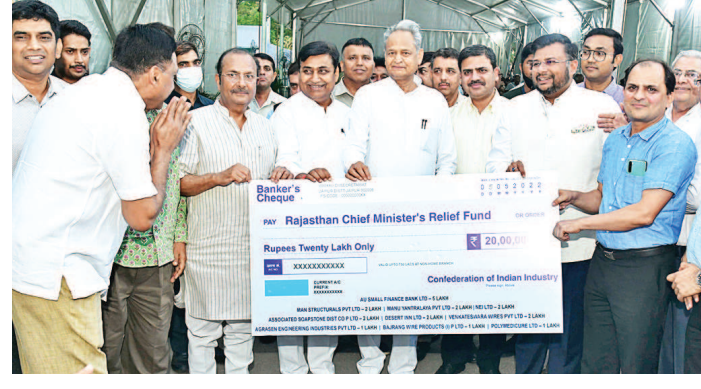
रिंगस गंगोरेप के अपराधियों को जेल भिजवाने के क्रांतिकारी कदम पर गोवर्धन सिंह जी के साथ जो अन्याय राजस्थान सरकार कर रही है उसे बदरस्त नहीं किया जाएगा अगर जल्द ही कोई सही कदम नहीं उठाया गया तो यह विरोध आंदोलन की तरफ बढ़ेगा। (हिलव्यू समाचार)

## मुख्यमंत्री निवास पर 'सेवांजलि' कार्यक्रम

# मुख्यमंत्री को मिले स्मृति चिह्न एवं उपहारों की नीलामी, लगभग 2 करोड़ रूपए मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए एकत्रित

शालिनी श्रीवास्तव

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले स्मृति चिह्न एवं उपहारों की नीलामी का कार्यक्रम 'सेवांजलि' गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित किया गया। भारत सेवा संस्थान की ओर से हुए इस कार्यक्रम में लगभग 2 करोड़ रूपए की राशि एकत्रित हुई। यह राशि 'निरोगी राजस्थान' के लिए 'मुख्यमंत्री सहायता कोष' में जमा होगा।



मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राजस्थान वर्षों से आपदा की घड़ी में सहयोग करने की महान परंपरा निभाता आ रहा है।

ने उदार मन से सहयोग किया। ऐसे सहयोग पर हम सभी को गर्व है। मुझे स्मृति चिह्न एवं उपहारों के जरिये प्रदेशवासियों ने जो सम्मान दिया है, वह प्रदेशवासियों के सहायतार्थ ही काम आएगा।

भारत सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष एवं राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने कहा कि राजस्थानियों ने आपदा के समय हमेशा सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया है। स्मृति चिह्नों की नीलामी से एकत्रित राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराकर 'निरोगी राजस्थान' बनाएंगे। उल्लेखनीय है कि स्मृति चिह्न एवं उपहारों की ऑनलाइन नीलामी भी की गई थी।

कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री बी.डी.कल्ला, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुट्टा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान हज कमेटी के अध्यक्ष अमीन कामजी, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत, आयोजक संस्थान के सचिव जी.एस बाफना, कोषाध्यक्ष एल.डी शर्मा सहित प्रदेश भर से सहयोगकर्ता उपस्थित थे।

## 5 पाक विस्थापित नागरिकों को मिली भारतीय नागरिकता जिला कलक्टर ने दी शुभकामना और कहा जिम्मेदार भारतीय नागरिक बने

हिलव्यू समाचार

जयपुर। जिला कलक्टर राजन विशाल ने गुरुवार को 5 पाक विस्थापित नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की। जिला कलक्टर ने भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करते हुये सभी को बधाई देते हुये जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनने की शुभकामना भी दी। इस अवसर पर प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारतीय नागरिक बन चुके इन 5 पाक नागरिकों में से 26 वर्षीय दीपक राम, जो 18 वर्ष पहले अपने परिवार सहित रहीम्यार खान (पाकिस्तान) से जयपुर आये थे। जो वर्तमान समय में जयपुर शहर में रहकर निजी क्षेत्र में कार्य कर

## नागौर पुलिस ने किया अवैध देह व्यापार का खुलासा, 4 महिलाओं समेत दो दलाल गिरफ्तार

नागौर। मानव तस्करी यूनिट नागौर तथा कुचेरा थाना पुलिस ने अवैध देह व्यापार का पर्दाफाश कर 4 महिलाओं और दो दलालों को गिरफ्तार किया है। नेशनल हॉस्टेल पर कुचेरा थाना क्षेत्र में बुटाटी गांव के पास एक होटल का संचालक बाहर से लड़कियां लाकर वेश्यावृत्ति करवा रहा था। पकड़ी गई युवतियां बंगाल और बिहार की रहने वाली हैं। नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि मानव तस्करी यूनिट के हेड कांस्टेबल बंसीलाल की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा के सुपरविजन एवं सीओ मूण्डवा विजय कुमार सांखला के नेतृत्व में कुचेरा थाना

## हनी ट्रैप में फंसा 10 लाख के लिए युवक को किया अगवा, चार आरोपी गिरफ्तार

हिलव्यू समाचार

झालावाड़। हनी ट्रैप में फंसा युवक को 10 लाख की फिरौती के लिए अगवा करने की घटना सामने आई है। युवक के पिता और साथ गए लोगों ने 3 लाख में राजीनामा कर 40 हजार रुपये देकर युवक को छोड़ा लिया। मगर बाकी 2.60 लाख रुपयों की मांग की धमकियों से परेशान होकर अंततः थाने पहुंचे और मामला दर्ज करवाया। बकानी थाना पुलिस ने मामले में तीव्र कार्रवाई कर रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिससे अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। झालावाड़ एसपी मोनिका सेन ने बताया कि 3 मई को पीड़ित फूलचंद लोधा निवासी गांव देवरी थाना रटलाई व एक अन्य थाना बकानी पहुंचे और एक रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया कि 26 अप्रैल की सुबह उसके मोबाइल पर एक महिला का कॉल आया और उसने शाम को रटलाई में पेट्रोल पंप के सामने मिलने बुलाया। शाम को वह बाइक से पेट्रोल पंप पहुंचा, जहां मिली महिला कब्जु बाई निवासी खैरदन्ता उसे साथ लेकर रामनिवास गांव की ओर ले गई। उस महिला ने खेत में रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाए। बाद में वह

## देवा गुर्जर हत्याकांड में वांछित 5000 इनामी गिरफ्तार

कोटा (हिलव्यू समाचार)। देवा गुर्जर हत्याकांड के संबंध में चित्तौड़गढ़ जिले के थाना रावतभाटा में दर्ज मुकदमे में वांछित चल रहे फरार मुलजिम भैरु लाल गुर्जर पुत्र गणेश लाल निवासी खेड़ा रुदा थाना चेचट को मण्डाना थाना पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी पर चित्तौड़गढ़ पुलिस द्वारा 5000 रुपए का इनाम घोषित है। वांछित आरोपी को पकड़ने में कांस्टेबल विपुल की विशेष भूमिका रही है। रुदल एसपी कावेन्द्र सिंह सागर ने बताया कि देवा हत्याकांड में शामिल वांछित इनामी अभियुक्त भैरु लाल गुर्जर पर कोटा ग्रामीण पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखी जाकर आ सूचना एकत्रित की जा रही थी। बुधवार को मण्डाना थानाधिकारी कल्याण सिंह को मुकुंदरा पहाड़ी के जंगलों में आरोपी के छुपे होने की सूचना मिली। इस सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत के सुपरविजन व सीओ ग्रामीण नेत्रपाल सिंह के निर्देशन और थानाधिकारी कल्याण सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने मुकुंदरा पहाड़ी के जंगलों में दबिश देकर आरोपी भैरु लाल गुर्जर को दस्तयाब कर लिया। अग्रिम कार्रवाई के लिए मामले में गठित एसआईटी को सूचित कर दिया गया है।



## जोधपुर हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा

हिलव्यू समाचार

जयपुर। उदयपुर दौरे के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के डर के चलते भाजपा प्रदेश में दंगे करवा रही है। सीएम गहलोत ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय से मांग की है कि एक कमेटी बनाकर इन दंगों की जांच करवाई जाए।

सीएम गहलोत ने गुरुवार को उदयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में दंगे किसी भी स्तर में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। करोली और जोधपुर में हुई हिंसा के लिए सीएम गहलोत ने भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भाजपा दंगे और धुवीकरण के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। सीएम गहलोत ने सभी राजनीतिक दलों से शांति की अपील करते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वह शांति व्यवस्था कायम करने में सहयोग करें।

सीएम गहलोत ने कहा कि भाजपा की योजना पूर्ण तरीके से पूरे प्रदेश में दंगा करवाने की है। पहले इन्होंने करोली में दंगा करवाया और अब जोधपुर में दंगा करवाया। पीएम ने कहा कि हमने पूरे प्रयास करके टाइम पर कार्रवाई की। इसलिए छुटपुट घटनाएं हुईं, कई जगह आगजनी भी हुई है जो भी लोग हिंसा में आरोपी है उन सब को अरेस्ट कर लिया गया है। हम किसी भी कीमत पर प्रदेश में हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो बीजेपी षड्यंत्र रही है उनके षड्यंत्र को भी कामयाब नहीं होने देंगे। सीएम ने कहा कि लेकिन यह बातें आज की युवा पीढ़ी को नहीं पता। इसीलिए भाजपा और आपएसएस के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और युवा पीढ़ी को बरगला रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि हिंसा में जो भी लोग दोषी हो चाहे वह किसी भी धर्म-मजहब या राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

लोधा के मार्फत पिता से बात की और 210 लाख लाने के लिए कहा और उसे बिंदा खेड़ा के जंगल में ले गए। अमर लाल उसके पिता नारायण लाल व गांव के ही रामप्रसाद को लेकर जंगल में आया और मध्यस्था कर 3 लाख में सोदा कर 40 हजार रुपये तीनों बदमाशों को दिला दिए। वैसे देकर वो अपने गांव आ गए। तबसे बदमाश अलग- अलग नंबरों से कॉल कर बाकी रुपयों के लिए धमका रहे हैं। इस रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अपराध की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार शर्मा के निर्देशन तथा सीओ नीरज कुमार शर्मा के सुपरविजन एवं थानाधिकारी मोहम्मद इब्राहिम के नेतृत्व में थाना बकानी से टीम गठित की जाकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना पुलिस ने तीव्र कार्रवाई कर महज 24 घंटों के अंदर रामपुरिया थाना भालता निवासी आरोपी बजरंग लाल उर्फ बरगद पुत्र भंवरलाल तंवर (28) एवं हजरीलाल पुत्र लालचंद तंवर (33) तथा नीचा खेड़ा थाना भालता निवासी कंवरलाल पुत्र पूरा लाल तंवर (55) एवं पथरिया थाना रटलाई निवासी अमर लाल लोधा पुत्र भैरुलाल (55) को गिरफ्तार कर लिया।

## आवासन आयुक्त ने किया 'परिंडा फॉर परिंडा' अभियान का शुभारम्भ

द्वारकादास पार्क में पक्षियों के लिये बांधे परिंडे जयपुर चौपाटी मानसरोवर व्यापार मण्डल की मानवीय पहल

हिलव्यू समाचार

जयपुर। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने गुरुवार को मानसरोवर चौपाटी के समीप द्वारकादास पार्क में परिंदों के लिये परिंडा लगाने के अभियान का शुभारम्भ किया। अरोड़ा ने पक्षियों के लिये वृक्षों पर परिंडा लगाकर और उसमें दाना-पानी भरकर अभियान की शुरुआत की।

आवासन आयुक्त ने जयपुर चौपाटी मानसरोवर व्यापार मण्डल की ओर से शुरू किये गये इस अभियान को सार्थक पहल बताया। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के समय में बेजुबान पक्षियों के लिये दाना-पानी की



व्यवस्था करना पुनीत कार्य है। आवासन आयुक्त ने सभी से अपनत्व की भावना रखते हुए परिंडों को संरक्षण देने की अपील की।

अरोड़ा ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनीयों में स्थित विभिन्न पार्कों में भी अभियान के तहत अधिक से अधिक परिंडे लगाये जाएं। उन्होंने इस अभियान के लिये जयपुर चौपाटी मानसरोवर व्यापार मण्डल के सदस्यों एवं सहयोगियों रोहित शर्मा, राकेश शर्मा, रोहित मंगल, प्रताप सिंह और योगेन्द्र गुप्ता आदि को बधाई दी। आवासन आयुक्त ने इससे

पूर्व आवासन मण्डल के प्रथम अध्यक्ष रहे स्वर्गीय द्वारकादास पुरोहित की प्रतिमा पर माल्यांजन भी किया। अभियान के संयोजक श्री रोहित शर्मा ने बताया कि इस अभियान के तहत द्वारकादास पार्क में 108 परिंडे, 51 चुंगा ट्रे और 21 घौंसले लगाए जाएंगे।

इस अवसर पर उप आवासन आयुक्त जे.एस. बुगालिया, आवासीय अभियानता राजेंद्र गुप्ता सहित आवासन मण्डल के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी वृक्षों पर परिंडे बांधे।

## राजस्थान आवासन मण्डल

हमारा प्रयास, सबको आवास

**अब! मात्र 11.55 लाख रुपये में**

**मात्र 409 शेष**

**900 वर्ग फीट पूर्ण निर्मित, रेडी-टू-शिफ्ट**

### सुरम्य वादियों के बीच

## MGD वीकेंड होम-नायला,

जयपुर में

**भारी छूट पर आवास खरीदने का सुनहरा मौका !**

(सीमित समय के लिए उपलब्ध)

**10% दीर्घ गृह-प्रवेश कीर्जिए**

**156 आसान मासिक किश्तों में भुगतान**

ई-मित्र पर मात्र ₹ 100 देकर ई-बिड सबमिशन में भाग लें

• योजना में पानी, बिजली, सड़क, सीवर, पार्क सहित मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था एवं ये आवास विवाद रहित है। • ई-बिड सबमिशन प्रत्येक सोमवार प्रातः 10.00 बजे से बुधवार सायं 4.00 बजे तक, आठवन प्रत्येक बुधवार सायं 4.30 बजे • जहां है जैसा है के आधार पर विक्रय • शनिवार/रविवार को आवास दिखाने की विशेष व्यवस्था

ऑनलाइन प्रस्ताव देने की प्रक्रिया के लिए आवासन मण्डल की वेबसाइट [www.urban.rajasthan.gov.in/RHB](http://www.urban.rajasthan.gov.in/RHB) देखें।

**हेल्पलाइन नं. कार्यालय समय में: 0141-2744688, 2740009, कार्यालय समय उपरान्त: 9461054291/92/319 एवं 9460254319, शांतनु वाणर्ष्य (9983131666), पवन सोनी (8852000770) या समन्वयक अधिकारी श्री भारत भूषण जैन (9828363615) से संपर्क करें**

RERA REG. NO. RAJ/RERA/P/2018/722 Rera Website: [www.rera.rajasthan.gov.in](http://www.rera.rajasthan.gov.in)



01

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Writ Contempt No. 400/2010

Goverdhan Singh son of Shri Bharat Singh, by caste Rajput, aged about 30 years, resident of nearby Narsingh Sagar Talab, Sarvodaya Basti, Bikaner, through Smt. Sushil Kanwar wife of Shri Goverdhan Singh, by caste Rajput, aged about 26 years, resident of nearby Narsingh Sagar Talab, Sarvodaya Basti, Bikaner.

Versus

- 1. Surjeet Singh Meena, presently Dy. Superintendent of Police, Sardar C.O., Police Station Sadar, District Bikaner.
- 2. Satish Chandra Jangid, presently Addl. Superintendent of Police (City), District Bikaner.
- 3. Dharam Puniya, presently S.H.O., of Nayashahar Police Station, District Bikaner.
- 4. Indra Singh, presently A.S.I., Police Station Nayashahar, District Bikaner.

-----Petitioner

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr.Goverdhan Singh, present in person

For Respondent(s) : Mr.K.L.Thakur, AAG with Mr.K.L.Vishnoi, Adv. Mr.Muktesh Maheshwari, Adv. Mr.Sarjeet Singh, Addl. S.P.,ACB, Bharatpur. Mr.Satish Chandra Jangid, Addl. S.P., SOG, Ajmer (retired) Mr.Dharam Puniya, Police Inspector, SHO, Nal, Bikaner. Mr.Bhojraj Singh, Dy. S.P., C.O., Sadar, Bikaner Mr.Indra Singh, S.I., P.S. Raisingh

(Downloaded on 05/08/2020 at 06:42:26 PM)

04

(4 of 6)

[WCP-400/2010]

The record of the SBCWP No.2360/2010 of which the order is under contempt be attached with the present petition."

Thereafter, when the matter came up on 03.07.2018, the petitioner was directed to file details of the FIR registered against him, the status of the FIR, the date on which the cancellation report was submitted. The needful has been done. From bare perusal of the detail placed before this Court in tabular form, it is apparent that cancellation report has been filed in all the cases at Serial No.14 (FIR No.97 dated 15.04.2012 filed against the petitioner at Bikaner). The cognizance has been taken in the said case and the petitioner has challenged the same in a revision petition before this Court, which is pending. In cases no. 4 to 13 of the table, protest petitions have been filed. Admittedly, the protest petitions have been filed way back in the year 2014. Thus, where the respondents /State is concerned, the matter stands closed and now, the matter is between the petitioner and the Court where the protest petition is pending since the year 2013/2014. Accordingly, this Court hopes that the respective courts shall decide the protest petitions as expeditiously as possible.

Mr. K.L.Thakur, learned Additional Advocate General states that sometimes the police officials are forced to re-open the case after complaint being filed by Smt. Kamla to the D.G.P. of Rajasthan and therefore, the directions are received for re-opening such cases. The lady Smt. Kamla is stated to be 87 years

(Downloaded on 05/08/2020 at 06:42:26 PM)

02

(2 of 6)

[WCP-400/2010]

HON'BLE MS. JUSTICE NIRMALJIT KAUR

Order

13/08/2018

While issuing notice on 13.09.2010, the learned Single Bench of this Court observed as under:-

When the order dtd. 8.9.2010 passed by this Court in the writ petition was submitted to the respondent No.2 Satish Chandra Jangid, Addl. S.P. (City), Dist. Bikaner and respondent No.3-Dharam Puniya, SHO, Police Station Nayashahar for needful compliance, they not only refused to comply with the order of this Court, but also asked the petitioner present in person Smt. Sushil Kanwar, and detained Sh. Poonam Singh for 4 hours and late in the evening on 9.9.2010 also registered a false FIR No.227/2010 against said Poonam Singh. The petitioner also submitted that they approached the Superintendent of Police, Bikaner, but still the compliance of the order of this Court could not be made and the vehicle Tata Safari as well as key of the residential house of the petitioner has not been returned back to them and all this happening because the husband of the petitioner Mr. Goverdhan Singh, an RTI activist took up the cudgels against them under the RTI Act. She also submitted that number of false FIRs has been lodged against her husband and family members and the respondents are hell bent upon harassing the family members of the petitioner. She has prayed that the respondents may be directed to remain present in the Court to report compliance of the directions of this Court and also an interim protection may be granted to the husband and other family members of the petitioner against the threatened arrest of said persons in the aforesaid false FIRs.

This Court passed a detailed order after hearing the petitioner on 8.9.2010 in presence of the respondent-contemnor Sh. Surjeet Singh Meena, Dy. Superintendent of Police, Police Station Sadar, Bikaner and since a responsible officer was present in the Court on the side of the respondents, it was naturally expected that the order would be communicated to the concerned persons for needful compliance. However, the allegations made in the present contempt petition is that the respondents No.2 and 3 when presented the said copy of order of this Court

(Downloaded on 05/08/2020 at 06:42:26 PM)

05

(5 of 6)

[WCP-400/2010]

old as informed by police officer Mr. Dharam Puniya, S.H.O. Nal, Bikaner. Obviously, the said complaint is not written by her but is being pursued by someone else through her. Therefore, the official should be careful in taking them up and proceeding without examining the truth of the such complaint. If any such complaint is received by any authority at her behest or on behalf of her

members, it would be proper that the said authority giving the complaint verifies the correct facts after calling the petitioner and hearing him before passing any order or initiating proceedings on the basis of the false complaint. It goes without saying that in case, such a complaint filed by anybody is found to be false by the police, they shall initiate proper proceedings in accordance with law against such persons filing false complaint.

In view of the above, this Court does not deem it proper to proceed with the contempt petition. The same is, accordingly, dismissed. Rule is discharged.

The petitioner who is present in person, however, expressed his concern about his safety and chances of his being enroped in false cases. Taking into account the past history of the various cases planted on the petitioner, which were found to be false and cancellation reports have been filed, this Court has already noticed in the last order that the petitioner was granted security if necessary by the order of this Court dated 17.02.2012 passed in S.B.Civil Writ Petition No.4624/2011. Accordingly, once again, this Court repeats that it is the duty of the respondent-State to make sure that the petitioner is not harmed in any manner.

(Downloaded on 05/08/2020 at 06:42:26 PM)

03

(3 of 6)

[WCP-400/2010]

not only tore the copy of the same, but did not comply with the orders of this Court."

Thereafter, on the last date of hearing i.e. on 18.05.2018, this Court further observed as under:-

"The petitioner is present in person. The entire story of his harassment at the hands of the police was submitted. Multiple cases were slapped on the petitioner. His house was racked. His vehicle was seized. His brother who went to give the order of the Court was taken in police custody. Thereafter, in pursuance to the orders of this Court, the house was got re-opened and vehicle was released. Meanwhile, the police knowingly well that there was no truth in the allegation and there was nothing to support the same, submitted cancellation reports in all the pending FIRs against the petitioner. The said cancellation reports are stated to be pending before the various courts. The respondent-contemnors in order to keep the sword hanging on the petitioner and in order to pressurize him so that he does not approach the Court and withdraw the present contempt petition, have re-opened some of the investigation.

The petitioner is, accordingly, directed to place on record in tabular form the details of the FIRs registered against him, the status of those FIRs, the date on which the cancellation report was submitted, the date when the said FIRs were re-opened, the courts in which they are pending. The needful be done within one week.

This Court may also note that in case, the allegations of the petitioner are prima facie found to be correct by this Court, it may require the registration of FIR or hand over the matter to CBI or in the alternative, order for judicial enquiry

It appears from the various orders of this Court as well as after hearing the petitioner that the respondents seem to have taken law into their hands and under the garb of the police uniform have played havoc with the life of petitioner and appeared to exceed their action beyond their public duty.

It is also brought to the notice of the Court that the petitioner was granted security, if necessary, by the order of this Court dated 17<sup>th</sup> February, 2012 passed in S.B.Civil Writ Petition No.4624/2011. It if is so, then it is the duty of the respondent-State to make sure that the petitioner is not harmed in any manner.

Put up on 3<sup>rd</sup> July, 2018.

(Downloaded on 05/08/2020 at 06:42:26 PM)

06

(6 of 6)

[WCP-400/2010]

The petitioner has further pointed out that he has filed an application before the D.G.P. of Rajasthan on 30.06.2018. However, He is at liberty to pursue the same in accordance with law before the concerned authority if so deemed fit.

At this stage, petitioner also stated that he should be awarded compensation for the harassment caused to him. No such order be passed in the present petition. However, the petitioner is at liberty to seek compensation and damages in accordance with law.

(NIRMALJIT KAUR),J

NK/1

(Downloaded on 05/08/2020 at 06:42:26 PM)







